नायडू ने पनामा शहर में राजनयिकों और छात्रों को संबोधित किया

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने वर्तमान विश्व में बढ़ते अलगाव पर चिंता व्यक्त की है जिनमें आपस में काफी जुड़ाव रहा है और उन्होंने गरीबी तथा असमानता जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत चाहता है कि एक नई विश्व व्यवस्था बने और कार्य देश के प्राचीन ज्ञान और मूल्यों पर आधारित हो, जो सौहार्दपूर्ण अस्तित्व और सार्वजनिक हित में हो।

उन्होंने 10 मई, 2018 को 'इन सर्च ऑफ ए मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड रेलिवेंट वर्ल्ड ऑर्डर' विषय पर पनामा शहर के छात्रों और विभिन्न देशों के राजदूतों से बात करते हुए वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत का दृष्टिकोण रखा।

श्री नायडू ने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति और ज्ञान के विस्तार ने साइबर सुरक्षा, आतंकवाद, परमाणु और रासायनिक आदि जैसी कई चुनौतियों को जन्म दिया है जिससे मानव अस्तित्व खतरे में पड़ा गया है। समकालीन मुद्दों पर उन्होंने आगे कहा कि भ्रष्टाचार, भेदभाव, शोषण, हिंसा और बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन दुनिया भर में सामाजिक ताने-बाने को खत्म कर रहा है। शोषण की धारणा और स्थापित शासन प्रणाली की विफलता अशांति, गुस्से, विद्रोह और चरमपंथ जैसी बुराईयों की वजह है। जितनी जल्दी हम इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से बात करेंगे, उतनी ही बेहतर सामूहिकता चिह्नित कर पायेंगे।

प्राचीन भारतीय ऋषि और वेदों का उद्धरण देते हुए श्री नायडू ने कहा कि भारत हमेशा प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है और इन मूल सिद्धांतों में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों को सामूहिक प्रयासों के जरिये हल करने की कुंजी है और इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने 'पृथ्वी सुक्तम' को उद्धृत किया जिसमें कहा गया है ईश्वर करे कि हमारे और धरती माता के बीच परस्पर क्रिया सौहार्दपूर्ण हो और वेदों को उद्धृत करते हुए कहा पूरे ब्रह्मांड में शांति का प्रवाह हो। उपराष्ट्रपति ने कहा विश्व व्यवस्था में हम चाहते हैं कि सत्ता और जिम्मेदारियां साझा की जायेंगी, विचारों और बात रखने का सम्मान किया जाता है तथा सम्पति व पृथ्वी के संसाधन साझा किए जाते हैं। श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि किसी भी देश या देशों के समूह को वैश्विक निर्णय लेने के लिए प्रभावित या नियंत्रित नहीं करना चाहिए और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर अधिक प्रतिनिधिक निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में तत्काल सुधार करना चाहिए।

श्री नायडू ने कहा भारत राष्ट्रीय हितों के लिए संतुलित प्रयास चाहता है, जो नई और बेहतर विश्व व्यवस्था का गठन करेगा।

40 देशों के राजदूतों ने श्री नायडू से बातचीत की और केंद्र सरकार की प्रमुख पहलों और उनके कार्यान्वयन तथा तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की।

बाद के दिन में, श्री नायडू ग्वाटेमाला और पनामा जाने के बाद दो दिनों के लिए पेरू की राजधानी लीमा पहुंचे।

राष्ट्रपति कोविंद 14 वर्षों के बाद सियाचिन की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज (10 मई 2018) सियाचिन बेस कैम्प की यात्रा की तथा वहां तैनात जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कुमार पोस्ट का भी दौरा किया। राष्ट्रपति कोविंद सियाचिन की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय राष्ट्रपति हैं। पिछली सियाचिन यात्रा अप्रैल 2004 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। इस प्रकार राष्ट्रपति कोविंद 14 वर्षों के बाद सियाचिन की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं।

जवानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में वे पूरे देश की कृतज्ञता को साथ लेकर आये हैं। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और विषम जलवायु में सामान्य जीवन जीना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में, सैनिकों के निरंतर लामबंद रहने और युद्ध के लिए तैयार रहना असाधारण बात है। उनका संकल्प और समर्पण अत्यधिक प्रशंसा के लायक है और भारत की सुरक्षा के प्रति उनकी निष्ठा हमारे नागरिकों के लिए एक आदर्श है।

पिछले 34 वर्षों से सियाचिन में पदास्थापित हमारे सैन्यकर्मियों की वीरता तथा पराक्रम ने प्रत्येक भारतीय को यह भरोसा दिया है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वे सियाचिन में सैन्यकर्मियों को यह संदेश देने आये हैं कि भारत के सभी नागरिक और भारत सरकार सदैव उनके तथा उनके परिजनों साथ हैं। राष्ट्रपति ने सियाचिन युद्ध स्मारक को श्रद्धांजलि दी। यह स्मारक सियाचिन में वीरगति को प्राप्त 11,000 सैन्यकर्मियों का प्रतीक है जिन्होंने 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेघदूत के बाद अपने प्राणों का बलिदान दिया है।

अल्पसंख्यक समुदायों के होनहार युवाओं को प्रोत्साहन और प्रगति सरकार की प्राथमिकता–नकवी

केद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि उनका मंत्रालय अल्पसंख्यक समुदायों के होनहार युवाओं के प्रोत्साहन और प्रगति के लिए प्रभावी प्रयास कर रहा है। श्री नकवी ने मंत्रालय के मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम की मदद से 2017 की प्रशासनिक सेवाओं में चयनित अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को आज नई दिल्ली में सम्मानित किया। यह कहते हुए कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय होनहार अल्पसंख्यक युवाओं के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के सहयोग से प्रशासनिक सेवाओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अन्य प्रशासनिक सेवाओं और बैंकिंग परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम चला रहा है, उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर वर्ग का कोई भी होनहार युवा सर्वश्रेष्ठ कोचिंग से वंचित न रहे और बेहतर नौकरी का मौका न गंवाए। श्री नकवी ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग में सफल युवा अल्पसंख्यक और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए अनुकरणीय उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों खासतौर से मुस्लिम युवाओं में अत्यधिक प्रतिभा है और ऐसा माहौल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे उनमें विश्वास पैदा हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की प्रतिभा की रक्षा करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का माहौल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं का शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं में चयन हुआ है। श्री नकवी ने कहा कि केन्द्र सरकार की बिना किसी भेदभाव के ''प्रतिष्ठा के साथ विकास'' की नीति ने यह सुनिश्चित किया है कि इस वर्ष आजादी के बाद पहली बार रिकार्ड संख्या में 51 मुस्लिमों सहित 131 अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशासनिक सेवाओं के लिए चयन किया गया है। श्री नकवी ने कहा कि पिछले वर्ष भी प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवाओं में 52 मुस्लिमों सहित 126 अल्पसंख्यक युवाओं का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्रशासनिक सेवाओं में 1099 लोगों का चयन किया गया, जिसमें 52 मुस्लिम युवा थे, जो कुल चयनित उम्मीदवारों का 4.5 प्रतिशत है। प्रतिशत के लिहाज से इस वर्ष कुल 990 सफल उम्मीदवारों में से मुस्लिमों का प्रतिशत 5.15 है। इस वर्ष तीन महिलाओं सहित 6 मुस्लिमों का रेंक शीर्ष 100 में रहा। श्री नकवी ने कहा कि उनका मंत्रालय यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से ताल्लुक रखने वाले होनहार युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम चला रहा है। विभिन्न संस्थानों और संगठनों के जरिए मंत्रालय प्रशासनिक सेवाओं, अन्य यूपीएससी परीक्षाओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई उड़ान, नया सवेरा जैसे कोचिंग कार्यक्रम चला रहा है। वर्ष 2017-18 के दौरान अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के प्रशासनिक सेवा परीक्षा की प्रारंभिक (प्रीलिमिनरी) परीक्षा पास करने वाले युवाओं को नई उड़ान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

सी. आर. आई. पम्पस ई.ई.एस.एल. के 150 करोड़ के ऑर्डर को कार्यान्वित करेगा

आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजी. डी. एस. एम.) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के एक उद्यम, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई. ई. एस. एल.) से सी. आर. आई. को 150 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। एजी. डी. एस. एम. कार्यक्रम का लक्ष्य मौजूदा अकुशल कृषि पंपों को बीईई पांच सितारा रेटेड ऊर्जा दक्ष पम्पसेट से बदलना है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सक्षम स्मार्ट कंट्रोल पैनलों के साथ 25 प्रतिशत की अनुमानित ऊर्जा बचत क्षमता है। ये पम्पसेट किसानों को पांच साल के मुफ्त रखरखाव के साथ निः शुल्क मुहैया कराए जाएंगे। परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश के 40,000 से अधिक किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

सी. आर. आई. पम्पस ने आठ साल पहले महाराष्ट्र में एक पायलट परियोजना की थी, यह ऑर्डर उसी परियोजना का परिणाम है- ऐसा काम करने वाली एकमात्र कंपनी, जिसे सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली खपत को कम करने के लिए भारत सरकार की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। बीईई स्टार रेटेड ऊर्जा दक्ष पम्पसेट की औसत दक्षता सीमा 40 से 50 प्रतिशत है जबकि मौजूदा पम्पसेट की दक्षता सीमा 20 से 30 प्रतिशत की है।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सौरभ कुमार ने कहा , एजी. डी. एस. एम. कार्यक्रम का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है क्योंकि कृषि पंपों के लिए बिजली बिलों को सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में, भारत में कृषि के लिए दो करोड़ से अधिक पंपों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रति वर्ष 173.2 बिलियन यूनिट बिजली की खपत करते हैं। प्रति वर्ष पांच लाख से अधिक नए पम्पसेट लगाए जा रहे हैं। (19-10)

सॉफ़्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध होने वाली 150 वीं कंपनी बन गई

अहमदाबाद, सॉफ़्टटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, सॉफ्टवेयर उत्पादों में नवप्रवर्तन से जुड़ी कंपनी, जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन ("AEC") वर्टिकल को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है, ने आज मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन एवं मूल्यांकन विभाग के कार्यालय के अधीन अपने ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक लागू किया, जो गुजरात राज्य के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन डेवलपमेंट परमिशन सिस्टम (ODPS) है। यह प्रणाली सीएडी भवन-निर्माण योजनाओं के सॉफ्टवेयर आधारित स्वचालित जांच में मदद करेगी, जिससे स्वीकृति मिलने का समय काफी कम हो जाएगा। इस प्रणाली को पूरे राज्य में 192 शहरी स्थानीय निकायों पर कार्यरत किया जाएगा।

ऑनलाइन डेवलपमेंट परमिशन सिस्टम (ODPS), भवन-निर्माण योजना की जांच एवं स्वीकृति की एक अभिनव प्रणाली है। यह CAD ड्रॉइंग को पढ़ता है और नगर निगम एवं अनुमोदन अधिकारियों द्वारा स्वीकृति के लिए विकास नियंत्रण नियमों के अनुरूप नक़्शा तैयार करता है। यह भवन-निर्माण योजनाओं के ई-गवर्नेंस के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में से एक है, जिसकी सेवाएं देशभर के कई ग्राहकों को उपलब्ध कराई गई हैं। यह संबंधित दस्तावेज़ जांच के साथ स्वीकृति प्रक्रिया की निगरानी के लिए निर्बाध रूप से एक ऑनलाइन अनुमोदन वर्कफ़्लो से जुड़ा होता है। इस प्रणाली से अनुपालन, दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार करने में मदद मिलती है। (3-1)

मालदीव के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) की संयुक्त निगरानी

भारतीय नौसेना का अपतटीय निगरानी पोत (एनओपीवी) सुमेधा को 9 से 17 मई, 2018 तक मालदीव के ईईजेड की संयुक्त निगरानी के लिए तैनात किया गया है। यह तैनाती नौसेना के मिशन आधारित तैनाती के हिस्से के रूप में की गई है। यह निगरानी पोत 11 से 12 मई, 2018 तक माले का संचालन भ्रमण करेगा जिसके दौरान यह पोत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बलों (एमएनडीएफ) के कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। समेधा एमएनडीएफ कर्मियों के साथ 12 से 15 मई, 2018 तक मालदीव के ईईजेड की संयुक्त निगरानी करेगा। एमएनडीएफ कर्मी ईईजेड निगरानी पूरी होने पर माले में पोत से उतर जायेंगे।

दो अधिकारी और भारतीय नौसेना के मरीन कमांडों (एमएआरसीओ) कैडर के 8 नाविक मालदीव में दूसरा विषम युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास (एकता 2018) संचालित कर रहे हैं। यह अभ्यास माले से 145 किलोमीटर उत्तर में कंपोजिट ट्रेनिंग सेंटर, माफिलहाफुशी में किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान एमएनडीएफ कर्मियों को गोताखोरी उपकरणों के इस्तेमाल और रखर-खाव, चिकित्सा आपात सहित गोताखोरी से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मालदीव में भारत के राजदूत ने भी 6 और 7 मई, 2018 को प्रशिक्षण अभ्यास देखा। भारतीय नौ सेना का सुमेधा पोत 15 मई, 2018 को माले में भारतीय नौसेना के मार्को प्रशिक्षण दल को अलग करेगा।

मालदीव ईईजेड की संयुक्त निगरानी द्वीप देश मालदीव के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए भारत सरकार और भारतीय नौसेना का प्रयास है।

संपादक–चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक–मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल–201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद–6. मालिक–कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, एच–47, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया।
फोन–26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

हम मार्च 2019 तक गंगा को 70 से 80 प्रतिशत स्वच्छ बनाने की आशा रखते हैं–नितिन गडकरी

हम मार्च 2019 तक गंगा को 70 से 80 प्रतिशत स्वच्छ बनाने की उम्मीद करते हैं। यह एक सामान्य धारणा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह सही नहीं है। 251 प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) को बंद किया गया है और जीपीआई के नियमों की अवहेलना करने के लिए उद्योगों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं उक्त बातें केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। यह संवाददाता सम्मेलन वीडियो के जरिये पटना, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर से जुड़ा था। मंत्री महोदय ने कहा कि 938 उपक्रमों में वास्तविक समय पर प्रदूषण की निगरानी की जा रही है। 211 ऐसे नालों की पहचान की गई है जो गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। नाले के पानी के परिशोधन के लिए 20 एसटीपी निर्मित किए गए हैं।

केन्द्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने कहा कि गंगा तट पर स्थित लगभग 4470 गांव खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो गए है। हम लोग अब ओडीएफ प्लस की रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। ठोस-द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, गांवों व शहरों को प्लास्टिक मुक्त बनाना तथा जन जागरूकता अभियान चलाना जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुश्री भारती ने कहा कि हमारा मंत्रालय गंगा ज्ञान परियोजना पर काम कर रहा है, जो गंगा तट पर बसे गांव के सम्पूर्ण विकास पर आधारित है। गंगा ग्राम में जैविक खेती, संरक्षण परियोजना, ठोस व द्रव अपशिष्ट का उचित निपटान तथा तालाबों के पुनरुद्धार पर विशेष जोर दिया जाएगा।

नमामि गंगे एक वृहद कार्यक्रम है जिसमें गंगा सरंक्षण से संबंधित सभी पुरानी व वर्तमान की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 20,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन अगले पांच वर्षों तक किया जाएगा और यह दिसम्बर 2020 को समाप्त होगा।

'नामिम गंगे कार्यक्रम' के तहत सीवर अवसंरचना, घाटों व श्मशान स्थलों का विकास, नटी तट विकास, नदी सतह की साफ-सफाई, जैव विविधता सरंक्षण, वानिकीकरण, ग्रामीण स्वच्छता जैसी गतिविधियों पर आधारित कुल 195 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

195 में से 102 परियोजनाओं के तहत 2369 एमएलडी क्षमता के नये सीवर शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा, 887 एमएलडी क्षमता वाले संयंत्रों की मरम्मत की जायेगी तथा गंगा व यमुना में प्रदूषण को कम करने के लिए 4722 किलोमीटर लम्बा सीवर नेटवर्क बनाया जायेगा। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत 2 एसटीपी परियोजनाएं (वाराणसी और हरिद्वार) हाईब्रिड एनयुटी पीपीपी मोड (एचएएम) के तहत चलाई जा रही है। एचएएम के तहत मंजूर की गई परियोजनाएं हैं- उत्तर प्रदेश में नैनी, झुसी, फाफमाऊ, उन्नाव, शुक्लगंज, मथुरा, कानपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और फररुखाबाद; बिहार में दीघा, कंकड़बाग और भागलपुर; पश्चिम बंगाल में हावड़ा, बाली और टॉली नाला (कोलकाता), कमरहटी और बड़ानगर।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 'एक नगर एक संचालक' को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत सात शहरों (कानपुर, इलाहाबाद, पटना, हावड़ा, भागलपुर, मथुरा और कोलकाता) के एसटीपी परियोजनाओं को एकीकृत किया गया है और एचएएम के तहत निविदा जारी की गई है। चार (कानपुर, इलाहाबाद, मथुरा और कोलकाता) के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत उन दस शहरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिनके द्वारा कुल सीवर का 64 प्रतिशत प्रवाहित होता है।

नदी तट विकास के तहत 152 घाटों तथा 54 श्मशान घाटों का विकास किया जा रहा है और इसके 2018 तक पूरे होने की उम्मीद है। इसकी अनुमानित लागत 683.32 करोड़ रुपये है। 254.52 करोड़ रुपये की लागत से पटना नदी तट विकास परियोजना पूरी होने के अंतिम चरण में है। इसके तहत 20 घाटों तथा 6.6 किलोमीटर लम्बा टहलने का मार्ग विकसित किया जा रहा है।

नमामि गंगे के तहत पानी की गुणवत्ता जांच के लिए 44 जल गुणवत्ता निगरानी प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा रहा है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत गंगा बेसिन में पांच करोड़ से ज्यादा पौधे लगाये गये हैं। उत्तराखंड में 31 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 13 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और शेष 18 निर्माण के विभिन्न चरणों पर है। जून 2018 तक ऋषिकेश, नवंबर 2018 तक जोशीमठ, श्रीनगर, हरिद्वार और दिसंबर 2018 तक बद्रीनाथ, चमोली, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, हरिद्वार में परियोजनाएं पूरी होने की संभावना है।

उत्तरप्रदेश में 30 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। 03 के निविदाओं की जांच की जा रही है। 10 के लिए निविदाएं जारी की जायेंगी। इलाहाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, अनूपशहर व नरोरा में परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद (सी एवं ई), मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर में परियोजनाएं शीघ्र ही पूरी हो जायेंगी। चुनार और मथुरा की निविदाओं की जांच की जा रही है।

बिहार में 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 10 परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। 04 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। 06 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जल्द ही जारी की जायेंगी। बक्सर तथा पटना के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर है। बाढ़, सुल्तानगंज, मोकामा, नौगछिया के लिए निविदाएं प्राप्त की जा चुकी है। भागलपुर, दीघा और कंकड़बाग (पटना) के लिए निविदाएं जारी की जायेंगी।

झारखंड के साहिबगंज में दो परियोजनाएं प्रगति पर हैं जहां 12 एमएलडी क्षमता वाले एक एसटीपी, 55 किलोमीटर लम्बे सीवर का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना दिसंबर 2018 तक पूरी हो जायेगी। राजमहल परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इसके तहत 3.5 एमएलडी एसटीपी तथा 34 किलोमीटर लम्बे सीवर का निर्माण किया जायेगा। इसके जून 201 9 तक पूरा होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में 15 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें से 2 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है। चार परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है जबकि चार अन्य निविदा की प्रक्रिया में हैं। पांच परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की जायेंगी।

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह को संबोधित किया

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के बाद भारत अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और ज्ञान उत्पादन में आगे बढ़ रहा है। आज, हमने संचार प्रौद्योगिकी, आईटी, फार्मास्युटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी में सर्वोत्तम श्रेणी की क्षमताओं में विस्तार किया है। इसने हमारे देश के बारे में धारणाओं को बदल दिया है और हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों की मदद की है। पिछले साल, हमने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली-1एल का शुभारंभ करके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हम चंद्रमा के लिए चंद्रयान-2 मिशन की तैयारी भी कर रहे हैं। इस समारोह में पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि हमारे नवाचार और प्रौद्योगिकी के प्रयासों में गुणवत्ता गैर-विचारणीय है। एक समय था जब हम जुगाड़ से मितव्ययी और कम लागत वाले अविष्कार करते थे- प्रौद्योगिकी के प्रति हमारा लघु, वृद्धि के आधार पर परिवर्तन या कट एंड पेस्ट दृष्टिकोण था। समाज के रूप में, हमारे पास है और हमें उस धारणा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के पुरस्कार विजेता उदाहरण है कि हम कैसे साहस के साथ, जोखिम लेने की क्षमता और सरलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम कल्पना और नवाचार के बीच कैसे दूरी बना रहे हैं। उत्पादों और प्रक्रियाओं से परे, यह हमारी प्रौद्योगिकी इनक्युबेटर के बीच नई ऊर्जा है। राष्ट्रपति ने कहा कि अब हमें नई सीमाओं का पता लगाना है। सरकार ने रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धि, डिजिटल निर्माण, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम संचार और चीजों के इंटरनेट में युवा तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। सरकार स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के लिए सफल प्रौद्योगिकी समाधानों और जल उपलब्धता की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रतिपादन और परिनियोजन कर रही है। ये 21 वीं सदी की चुनौतियां है और 21 वीं सदी में ही इसके जवाब की आवश्यकता है।

स्मार्ट्रॉन ने टी बैंड लॉन्च किया

भारत के पहले ग्लोबल टेक्नॉलॉजी ओईएम एवं प्रीमियर आईओटी ब्रांड, स्मार्ज़्ट्रॉन ने आज अपनी पहली वियरेबल डिवाईस, टीबैंड के लॉन्च की घोशणा की। थकावट और तनाव को नापने के लिए ईसीजी (इलेक्ट्रोकॉर्डिज़्योग्राम) एवं बीपी (ब्लड प्रेषर) मॉनिटरिंग जैसी विषेशताओं के साथ यह टीबैंड केवल फ्लिपकाटज़ पर 13 मई, 2018 को रात्रि 12:01 बजे से 4,999 रु. में मिलेगा।

टीबैंड लॉन्च करते हुए रोहित राठी, प्रेसिडेंट एवं को-फाउंडर, स्माज़्ट्रॉन ने कहा, ''स्माज़्ट्रॉन पर हमारा केंद्रण ऐसे उत्पादों के विकास पर है, जो टेक्नॉलॉजी में अत्याधुनिक होने के साथ ग्राहकों को सेवाओं और समाधानों का पूरा परिवेष प्रदान करते हैं। टीबैंड के साथ भी हमने श्रेणी की प्रथम विषेशताओं जैसे ईसीजी एवं बीपी मॉनिटरिंग का समावेष किया है, जो हाई-एण्ड उत्पादों में भी उपलब्ध नहीं हुआ करती हैं। हम एक मजबूत ट्रॉनएक्स हेल्थ पोटज़्फोलियो बनाना चाहते हैं और यह उस दिषा में हमारा पहला कदम है। हमें उम्मीद है कि इस लॉन्च के बाद स्वास्थ्य के दृश्टिकोण में बदलाव आएगा। यह टीबैंड उन लोगों के लिए बनाया गया है, जो न केवल अपनी एक्टिविटी और कैलोरी काउंट मापना चाहते हैं, बल्कि हेल्ड इंडेक्स के माध्यम से हेल्थ का व्यवहारिक संकेत देखना भी चाहते हैं। इस टीबैंड में प्रतिघंटा एचआरएम, स्लीप एफिषियंसी, तनाव एवं थकावट की मॉनिटरिंग जैसी विषेशताएं हैं, जिनमें से सभी सेहतमंद जीवन के लिए बहुत महत्वपूणज़ हैं।''(19-10)

रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल शिवाजी को बहादुरी के लिए रेल मंत्री के पदक से सम्मानित किया जाएगा

रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल श्री शिवाजी को बहादुरी के लिए एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ रेल मंत्री के पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार बल के उस सदस्य को दिया जाता है जिसने बल के सदस्य के रूप में अत्यंत साहस, कौशल अथवा बहादुरी का परिचय देते हुए ड्यूटी के प्रति विशिष्ट समर्पण की भावना प्रदर्शित की हो।

आरपीएफ कांस्टेबल श्री शिवाजी 23.04.2018 को दक्षिणी रेलवे में वेलाचारी स्टेशन से ट्रेन में पहरेदारी कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन चिंताड्राइपेट स्टेशन से रवाना हुई उन्हें रात में करीब पौने बारह बजे साथ के डिब्बे से एक महिला के चीखने की आवाज सुनाई दी। आरपीएफ कांस्टेबल श्री शिवाजी अगले स्टेशन यानि पार्क टाउन स्टेशन पर उस डिब्बे में गए। यह देखने पर की एक पुरुष महिला का यौन उत्पीडन कर रहा है। वे तत्काल हरकत में आ गए। उन्होंने अपराधी को पकड़ा और महिला को छुड़ा लिया। अपराधी को तत्काल रेलवे पुलिस, चेन्नई एगमोर (जीआरपी) को सौंप दिया गया और श्री शिवाजी की शिकायत पर एक एफआईआर दायर की गई। महिला को चिकित्सा के लिए चेन्नई स्थित राजीव गांधी अस्पताल ले जाया गया।

एक महिला यात्री को बचाने के लिए समय पर की गई कार्रवाई के कारण श्री शिवाजी ने अनेक लोगों का दिल जीत लिया।

सुरक्षा में सुधार की दिशा में दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा हाथ में ली गई गतिविधियां और निरंतर प्रयास

बजटीय व्यय कुछ वर्ष पहले 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर करीब 3000 करोड़ रुपये किया गया।

सभी मानव रहित फाटकों पर 24 घंटे गेट मित्रों की तैनाती

2017-18 में 25 के लक्ष्य को सामने रखते हुए आरओबी/आरयूबी/सबवे के निर्माण द्वारा 27 मानव रहित फाटकों को हटाया गया

राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष - मंत्रालय ने कोष की स्थापना 2017-18 के बजट में की। इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 2017-18 में 687 करोड़ रुपये का कोष बनाया। सुरक्षा के लिए इस कोष की अधिकांश राशि पटरियों को नए सिरे से बनाने और उनके उन्नयन में खर्च की जा रही है।

सुरक्षित एलएचबी कोचों की तरफ झुकाव

रखरखाव सुविधाओं में ढांचात्मक वृद्धि

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 2017-18 में 202 ट्रेक किलोमीटर पूरे किए, जो उसके इतिहास में सबसे अधिक है यानि 2016-17 के आंकड़ों की तुलना में करीब 115 प्रतिशत अधिक है।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई–निविदा सूचना
सं.: जेयू–09–2018–19
भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनके लिए मंडल रेल प्रबन्धक/सं.व.दू.उ.प.रे., जोधपुर द्वारा निम्न लिखित सिगनलिंग एवं टेलीकॉम सम्बन्धी कार्य हेतु मुहरबंद ई निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **1. कार्य का नाम:** उ.प.रेलवे जोधपुर मंडल के 09 स्टेशनो (राईकाबाग पैलेस, मंडोर, मारवाड़ मथानिया, तिवरी, ओशिया, भकमकोर, सामराउ, मारवाड़, लोहावट, व शैतानसिंह नगर) पर एस एस आई (सोलिड स्टेट इन्टरलॉकिंग प्रणाली) (अन्सालडो मैक) का तीन वर्ष हेतु वार्षिक अनुबन्ध का कार्य। **2. कार्य की अनुमानित लागत:** रूपये 10109046/–; **3. ई निविदा जमाकर्ता कार्यालय का पूर्ण पता:** वरि. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी. मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय हरीश जौशी मार्ग जोधपुर। **4. बयाना राशि (EMD):** रूपये 200550/–; **5. ई निविदा प्रपत्र जमा कराने एवं खुलने की तारीख व समय:** 13.06.2018 को 15.00 बजे तक। तथा ई टेंडर ऑन लाईन आई आर ई पी एस 15.00 बजे बन्द होने के तुरन्त बाद खोली जायेगी। **6. वैब साईट विवरण एवं नोटिस बोर्ड व कार्यालय जहाँ से टेण्डर का विवरण देखा जा सके। एवं खरीद की जा सके: www.ireps.gov.in**
नोट:– यह एक ई टेण्डर हैं इसलिए इसमें भाग लेने के लिए ठेकेदार ई टेण्डरिंग के द्वारा उल्लेखित वैब साईट पर टेण्डर डाले। **7. न्यूनतम मॉप दण्ड:** निविदा प्रपत्र अनुसार।
534-AD/18
हमें /NWRailways पर फॉलो करें

सूचना
कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई–मेल पर ही भेजें :
alpaviram@gmail.com